ज्ञान तत्व 383

मंथन क्रमांक 108– आरक्षण

कुछ स्वीकृत निष्कर्ष है।

1 किसी भी प्रकार का आरक्षण घातक होता है, वर्ग विद्वेष वर्ग संघर्ष का आधार होता है। आरक्षण पूरी तरह समाप्त होना चाहिये।

2 किसी भी प्रकार का आरक्षण समाज मे शराफत को कमजोर तथा धूर्तता को मजबूत करता है।

3 आरक्षण सिर्फ व्यक्ति की प्रवृत्ति के आधार पर दिया जाना चाहिये। कानून का पालन करने वालो को सुरक्षा का आश्वासन ही एक मात्र आरक्षण दिया जाना चाहिये।

4 आरक्षण हमेशा घातक होता है। स्वतंत्रता पूर्व का जातीय अथवा परिवार व्यवस्था मे पुरूषो को प्राप्त सामाजिक आरक्षण भी घातक था और स्वतंत्रता के बाद का संवैधानिक आरक्षण भी घातक है।

5 संविधान के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को समान अधिकार प्राप्त है । आरक्षण उस समानता को अ समान बना देता है।

6 जातीय आरक्षण, महिला आरक्षण, धार्मिक आरक्षण अथवा गरीबी आरक्षण के दुष्परिणाम स्वाभाविक होते है। भारत इन दुष्परिणामो की चपेट मे है।

7 किसी भी प्रकार के अन्य आरक्षण की तुलना मे महिला आरक्षण अधिक घातक है। अन्य आरक्षण समाज को तोडते है और महिला आरक्षण परिवार को ।

8 स्वतंत्रता के पूर्व भी श्रम के विरूद्ध बुद्धिजीवियो ने आरक्षण प्राप्त कर लिया था तथा स्वतंत्रता के बाद भी श्रमजीवियो के खिलाफ बुद्धिजीवियो का आरक्षण जारी रहा । यह आरक्षण अंबेडकेर जी का षणयंत्र था।

9 भारतीय राजनैतिक व्यवस्था मे सबसे अधिक घातक भूमिका अम्बेडकर जी की रही है। उन्होने निरंतर जान बूझकर सत्ता की लालच मे समाज को खंड खंड करने का काम किया ।

10 वर्तमान समय मे सवर्णो द्वारा आरक्षण का विरोध स्वार्थ पूर्ण है, क्योकि वे सिर्फ जातीय आरक्षण का विरोध करते है। महिला आरक्षण धार्मिक आरक्षण आर्थिक आरक्षण का नही करते है।

हजारो वर्षो से पूरी दुनियां मे श्रम शोषण के नये नये तरीके बुद्धिजीवियो द्वारा खोजे जाते रहे है। भारत मे भी यह प्रकृया लम्बे समय से चलती रही है और आज भी जारी है। स्वतंत्रता के पूर्व बुद्धिजीवियो ने जन्म के आधार पर वर्ण और जाति बनाकर श्रमशोषण का रास्ता खोला था। इसी तरह पूरूष प्रधान व्यवस्था भी मजबूत की गई थी । स्वतंत्रता के बाद भी बुद्धिजीवियो का उददेश्य श्रम शोषण ही रहा किन्तु स्वरूप बदल दिया गया। बुद्धिजीवियो ने अम्बेडकर जी के नेतृत्व मे श्रम के विरूद्ध सफल षणयंत्र किया और सवर्ण बुद्धिजीवी तथा अवर्ण बुद्धिजीवी के बीच समझौता कराकर जातीय आरक्षण का एक नया कानून लागू कर दिया गया। श्रम के प्रति न्याय होता तो श्रम मूल्य वृद्धि के प्रयत्न होते किन्तु ऐसे प्रयत्नो को रोकते हुए जातीय आरक्षण लागु कर दिया गया। इस आरक्षण को लगातार आज भी जारी रखा जा रहा है। एक नया आरक्षण महिलाओ के नाम से लाने का प्रयत्न हो रहा है। उचित होता कि महिलाओ को पारिवारिक व्यवस्था मे समान भूमिका दे दी जाती तथा परिवार की संपूर्ण सम्पत्ति मे भी बराबर का अधिकार दे दिया जाता। सारे विवाद खत्म हो जाते । किन्तु महिला आरक्षण के नाम पर कुछ न कुछ समस्याओ के विस्तार का षणयंत्र चलता रहता है। हिन्दू मुसलमान के नाम पर भी आरक्षण की आवाज उठती रहती है। यदि सबको समान अधिकार मिल जाता तो यह समस्या पैदा ही नही होती । गरीबो की सहायता के नाम पर भी आर्थिक आरक्षण की बात उठती रहती है। यदि कृत्रिम उर्जा का मूल्य बढा दिया जाता तो गरीब अमीर की खाई अपने आप खत्म हो जाती और श्रम का मूल्य बढ जाता । ग्रामीण उधोग मजबूत हो जाते और शहरी आबादी अपने आप संतुलित हो जाती किन्तु आर्थिक आरक्षण के नाम पर यह षणयंत्र भी अब तक जारी है। भारत का हर बुद्धिजीवी किसी न किसी आधार पर आरक्षण का समर्थन करता है। क्योकि आरक्षण के नाम पर कमजोरो का शोषण करने का बुद्धिजीवियो को अप्रत्यक्ष लाभ भी होता है तथा साथ ही कमजोरो की मदद करने से उनकी सहानुभूति का प्रत्यक्ष लाभ भी मिलता है । यही कारण है कि भारत का हर बुद्धिजीवी किसी न किसी रूप मे भीम राव अंबेडकर का प्रशंसक है, क्योकि सब प्रकार के आरक्षण के मार्ग खोलने का पहला श्रेय भीम राव अम्बेडकर को जाता है। यहां तक कि नरेन्द्र मोदी तथा संघ परिवार भी अंबेडकर के प्रशंसक बन गये है।

किसी भी प्रकार का आरक्षण वर्ग विद्वेष का महत्वपूर्ण आधार बन जाता है। वर्ग विद्वेष को योजना पूर्वक बढाया जाता है और उसके दुष्परिणामो से सुरक्षा का ढोंग भी साथ साथ किया जाता है। यदि वर्ग विद्वेष पैदा ही न हो तो किसी प्रकार के समाधान की आवश्यकता ही नही है। किसी भी प्रकार का आरक्षण हमेशा धूर्तता और अपराधो का विस्तार करता है। जिस वर्ग को आरक्षण प्राप्त होता है उस वर्ग के धूर्त भिन्न वर्ग के शरीफो का शोषण करने का अधिकार प्राप्त कर लेते है। इस तरह शराफत कमजोर होती जाती है और धूर्तता मजबूत। आज भारत का हर बुद्धिजीवी अधिक से अधिक चालाक होने का प्रयत्न कर

रहा है जिससे वह मजबूतो के शोषण से बच भी सके और कमजोरो का शोषण कर भी सके। व्यवस्था लगातार टूट रही है धूर्तता मजबूत हो रही है।

कुछ लोग जातीय आरक्षण का विरोध कर रहे है। ये लोग सब प्रकार के आरक्षण का विरोध न करके सिर्फ जातीय आरक्षण का विरोध करते है क्योकि स्वतंत्रता के पूर्व उन्हे शोषण का एकाधिकार प्राप्त था । स्वतंत्रता के बाद उस एकाधिकार मे से थोडा सा हिस्सा अवर्णो के खाते मे चला गया। ऐसे लोग समान नागरिक संहिता के लिये कोई आंदोलन नही करते न ही कृत्रिम उर्जा मूल्य वृद्धि के लिये करते है। ऐसे लोग महिला आरक्षण गरीबो का आरक्षण धार्मिक आरक्षण का भी खुला विरोध नही करते। कुछ लोग हिन्दू राष्ट की मांग करते हे तो कुछ अन्य लोग मुसलमानो का आरक्षण देना चाहते है। अनेक लोग महिला सशक्तिकरण का नारा लगाते है तो अनेक लोग गरीबो को आर्थिक आरक्षण देने की वकालत करते है । जबकि स्पष्ट दिखता है कि किसी भी प्रकार का आरक्षण हमेशा घातक होता है । अधिकार प्रत्येक व्यक्ति के समान होते है। किसी को भी विशेष अधिकार देते है तो समानता का सिद्धान्त अपने आप खंडित हो जाता है। किसी विशेष स्थिति मे किसी की सहायता की जा सकती है और की जानी चाहिये किन्तु अधिकार किसी को अलग से नही दिये जा सकते ।

मै लम्बे समय से आरक्षण का विरोधी रहा हूँ और आज भी हूँ । मै अपने व्यक्तिगत जीवन मे प्रयत्न करता हूँ कि जो अवर्ण जातीय आरक्षण का समर्थन करते है उन्हे अछूत मानू और उनसे दूरी बनाकर रखूं। इसी तरह जो महिलाएं महिला सशक्तिकरण और महिला आरक्षण का समर्थन करती है उन्हे अपने घर मे न घुसने दूं क्योकि वे समाज के लिये गंभीर समस्या है । जो हिन्दू या मुसलमान धार्मिक आधार पर आरक्षण की मांग करते है उनसे भी अधिक से अधिक दूरी बनाकर रखता हूँ। जो लोग गरीब और अमीर के बीच मे समाज को विभाजित करना चाहते है उन्हे भी मै खतरनाक मानता हूँ। मेरे विचार से सब प्रकार के आरक्षण समाप्त करके नयी व्यवस्था शुरू होनी चाहिये, जिसमे 1 समान नागरिक संहिता हो । व्यक्ति एक ईकाई हो। धर्म जाति, गरीब अमीर, महिला पूरूष का भेद न हो। 2 कृत्रिम उर्जा की भारी मुल्य वृद्धि करके सब प्रकार के टैक्स तथा सबसीडी समाप्त कर दी जाये। 3 परिवार की आर्थिक और पारिवारिक व्यवस्था परंपरागत की जगह लोकतांत्रिक हो । परिवार मे व्यक्ति का सम्पत्ति अधिकार सामूहिक हो और सम्पूर्ण सम्पत्ति मे सिर्फ परिवार छोडते समय उसे बराबर का हिस्सा दिया जाये। इन सब सुधारो मे भी समान नागरिक संहिता तथा कृत्रिम उर्जा मूल्य वृद्धि विशेष महत्व रखते है। जो बुद्धिजीवी कृत्रिम उर्जा मूल्य वृद्धि या समान नागरिक संहिता का विरोध करते है ऐसे श्रम शोषक बुद्धिजीवियो से दूरी बनाकर रखनी चाहिये। अंत मे मेरा यह सुझाव है क किसी भी प्रकार के आरक्षण का पूरी तरह विरोध करना चाहिये। मै ऐसे विरोध का पक्षधर हूँ।

मंथन कमांक 109– ''भारत की आदर्श अर्थनीति''

कुछ स्वीकृत निष्कर्ष हैः–

1. आर्थिक समस्याओं का सिर्फ आर्थिक समाधान होना चाहिये। किसी भी परिस्थिति में प्रशासनिक समाधान उचित नहीं हैं;
2. भारत जैसे देश में आर्थिक दृष्टि से मजबूत लोगों पर कर लगाकर कमजोर लोगों को कर मुक्त करना चाहिये। वर्तमान समय में इसका उल्टा हो रहा हैं;
3. आर्थिक विषमता बहुत बडी समस्या होती हैं। आर्थिक विषमता को कम किया जाना चाहिये;
4. हजारों वर्षों से बुद्धिजीवियों ने श्रम शोषण के अनेक तरीके खोजे और उनका लाभ उठाया। वर्तमान भारत में भी बुद्धिजीवियों द्वारा श्रम शोषण के नये–नये तरीके खोजे जा रहैं हैं।
5. राज्य को सिर्फ सुरक्षा और न्याय तक सीमित रहना चाहिये राज्य को कभी समाज सुधार अथवा व्यापार नहीं करना चाहिये;
6. भारत की संवैधानिक व्यवस्था में विधायिका कार्यपालिका और न्यायपालिका के समान ही एक स्वतंत्र अर्थपालिका भी होनी चाहिये जिस पर संविधान के अतिरिक्त किसी अन्य का नियंत्रण न हो;
7. कोई भी बुद्धिजीवी श्रम के साथ न्याय के प्रयत्न नहीं करता। हर बुद्धिजीवी कृत्रिम उर्जा मूल्य वृद्धि का विरोध करता हैं क्योंकि कृत्रिम उर्जा मूल्य वृद्धि श्रम की मांग और श्रम का मूल्य बढाने में सहायक हैं;
8. सभी प्रकार के कर हटाकर एक सुरक्षा कर होना चाहिये जो सम्पत्ति कर के रूप में हो सकता हैं;
9. किसी प्रकार की सुविधा के लिये सरकार को फीस लेने की व्यवस्था करनी चाहिये, टैक्स नहीं;
10. राज्य की भूमिका सुरक्षा का वातावरण बनाने तक सीमित होती हैं। सुरक्षित रहना व्यक्ति का व्यक्तिगत कार्य हैं।
11. सुरक्षा में बाधा की स्थिति में राज्य को मुआवजा देना चाहिये। अन्य किसी प्रकार का मुआवजा बंद कर दिया जाये;

12. सुरक्षा का अर्थ सुरक्षित रखना नहीं हैं बल्कि सुरक्षा की बाधाओं को दूर करना हैं। राज्य को कभी सुरक्षा नहीं देनी चाहिये बल्कि बाधाओं को दूर करना चाहिये;
भारत में अर्थव्यवस्था पूरी तरह विपरीत दिशा में जा रही हैं। समाजवाद, साम्यवाद, पूंजीवाद जैसे दुनियां के अनेक वादों के चक्कर में भारत की अर्थव्यवस्था चौपट हो गयी हैं। समाजवादी और साम्यवादी अर्थव्यवस्था में सरकारीकरण को मजबूत किया तो पूंजीवाद ने सरकारीकरण को तो कमजोर किया किन्तु आर्थिक असमानता को मजबूत किया। आदर्श स्थिति में अर्थव्यवस्था न तो पूरी तरह सरकार के अधीन होनी चाहिए न ही पूरी तरह बाजार के अधीन।

भारत में एक बडी समस्या श्रम शोषण की हैं। गरीब, ग्रामीण, श्रमजीवी और कृषि उत्पादन पर भारी कर लगाकर बुद्धिजीवियों, पूंजीपतियों, उपभोक्ताओं तथा शहरी लोगों ने आर्थिक विषमता भी बढाई हैं और श्रम शोषण भी किया हैं। इन दोनों समस्याओं से निपटना न्याय संगत हैं। इसके लिए राज्य को अल्पकाल के लिये विशेष प्रवाधान करना चाहिये जिसमें सब प्रकार के कर हटाकर एक कृत्रिम उर्जा कर इस प्रकार लगाया जाये ताकि उसका कोई भी धन सरकारी खजाने में न जाये। बल्कि वह प्रत्येक नागरिक में इस तरह बराबर–बराबर बाँट दिया जाये जिसके परिणामस्वरूप श्रम का मूल्य बढे, शहरी आबादी घटे, कृत्रिम उर्जा का उपयोग नियंत्रित हो जाये, विदेशी कर्ज घट जाये, पर्यावरण सुधर जावें। यदि कृत्रिम उर्जा का मूल्य भारत में आपातकाल समझ कर ढाई गुना कर दिया जाये तो आर्थिक विषमता भी बहुत कम हो जायेगी अन्य अनेक समस्यायें अपने आप घटेगी।

सरकार का काम न तो सुविधा देना होता हैं न ही सुरक्षित रखना। सरकार का सिर्फ एक काम होता हैं अपराध नियंत्रण जिसका अर्थ होता हैं व्यक्ति की स्वतंत्रता में आने वाली किसी भी बाधा को दूर करना। राज्य वर्तमान समय में अपराध नियंत्रण छोडकर हर मामले में हस्तक्षेप करता हैं। वह व्यक्ति को सुरक्षा देता हैं और सुविधा भी देता हैं जो उसका काम नहीं हैं। इस तरह यदि राज्य स्वयं को अपराध नियंत्रण तक सीमित कर लेगा तो राज्य का बजट बहुत कम हो जायेगा और कर भी बहुत कम लगाना पडेगा। राज्य को सिर्फ सम्पत्ति कर के रूप में एक कर लेकर अन्य सारे कर समाप्त कर देना चाहिये। राज्य को पुलिस, सेना और न्याय का बजट सम्पत्ति कर के रूप में पूरा करना चाहिये क्योंकि राज्य प्रत्येक व्यक्ति के जान–माल की सुरक्षा की गारंटी देता हैं। अन्य किसी प्रकार का होने वाला खर्च फीस के रूप में लिया जा सकता हैं चाहैं शिक्षा और स्वास्थ्य हो अथवा अन्य कोई भी सुविधा।

मैं जानता हूँ कि भारत का कोई पूंजीपति सम्पत्ति कर से सहमत नहीं होगा भले ही उसे कुछ भी करना पडे। इसी तरह भारत का कोई भी बृद्धिजीवी कृत्रिम उर्जा मूल्य वृद्धि से भी सहमत नही होगा क्योंकि ये दोनों सुझाव दोनों प्रकार के लोगों अर्थात पूंजीपतियों, बुद्धिजीवियों के लिये घातक हैं। इस सुझाव के आधार पर आवागमन मंहगा हो जायेगा शहरी उद्योग गांव की ओर चले जायेगें मशीनीकरण घट जायेगा तथा श्रम बहुत मंहगा हो जायेगा जो न कोई बुद्धिजीवी चाहता हैं न ही पूंजीपति। भारत का हर बुद्धिजीवी गरीबी दूर करने और अमीर–गरीब के बीच टकराव वर्धक सुझाव पर विश्वास करता हैं लेकिन समाधान की चर्चा नहीं करता हैं। क्योंकि समाधान उनकी सुविधाओं में कटौती कर देगा और उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं पर प्रश्न चिन्ह खडा करेगा। भारत का हर समाजवादी प्रशासनिक तरीके से आर्थिक समस्याओं के समाधान की बात करता हैं और किसी भी प्रकार के निजीकरण के विरूद्ध होता हैं। इसी तरह भारत का हर वामपंथी पूंजीवाद का विरोध करता हैं, श्रमजीवियों के समर्थन का नाटक करता हैं, अमीरी रेखा और गरीबी रेखा के लिये आंदोलन करता हैं, किन्तु कृत्रिम उर्जा की मूल्य वृद्धि के विरोध में सबसे आगे रहता हैं क्योंकि समस्या का जीवित रहना ही उसके अस्तित्व के लिये आवश्यक हैं। सभी राजनैतिक दल आर्थिक समस्याओं का प्रशासनिक समाधान करना चाहते हैं, आर्थिक नहीं।

मेरा सुझाव हैं कि 1–राज्य का सारा खर्च सुरक्षा और न्याय तक सीमित करके सिर्फ सम्पत्ति कर के रूप में पूरा किया जाना चाहिये। 2–एक स्वतंत्र अर्थपालिका होनी चाहिये जो राज्य के आय–व्यय की समीक्षा करे और उसका बजट बनावें। 3–श्रम के साथ न्याय हो इसे सर्वोच्च प्राथमिकता देनी चाहिये और इसके लिये कृत्रिम उर्जा की भारी मूल्य वृद्धि होनी चाहिये तथा देश का निर्यात इतना अधिक बढाया जाये कि उपभोक्तावाद पर अकुंश लगे और उत्पादक सुखी हो। 4–समाजवाद, साम्यवाद और पूंजीवाद जैसी बुराईयों से पिंड छुडाकर हमें समाजीकरण की दिशा में बढना चाहिये जिसका अर्थ हैं प्रत्येक गांव को संवैधानिक, राजनैतिक और आर्थिक स्वतंत्रता। मेरे विचार से यह सुझाव आदर्श अर्थव्यवस्था के लिये मील का पत्थर बन सकता हैं।

आदर्श स्थिति तो सम्पूर्ण समाजीकरण ही हैं जिसमें अन्य मामलों के अतिरिक्त आर्थिक स्वतंत्रता से भी राज्य का हस्तक्षेप समाप्त हो कर समाज का नियंत्रण होना चाहिये किन्तु व्यावहारिक रूप से अभी तत्काल ऐसी संभावना नही हैं। इस लिये तात्कालिक रूप से हमें ऐसी नीति बनानी चाहिये जिससे आर्थिक मामलों में राज्य का हस्तक्षेप और शक्ति कम होती चली जाये। जो लोग अमीरी या गरीबी रेखा के नाम पर राज्य को अधिक शक्तिशाली बनाने के पक्षधर हैं वे गलत हैं। सम्पत्ति कर के नाम पर राज्य को मनमानी करने के अधिकार देना भी उचित नहीं हैं तथा कृत्रिम उर्जा की मूल्य वृद्धि करके राज्य अपना खजाना भरता रहैं ऐसी मांग का समर्थन भी करना उचित नहीं हैं। राज्य के आर्थिक अधिकार समाज नियंत्रित होने चाहिये और राज्य सम्पत्ति कर तथा कृत्रिम उर्जा मूल्य वृद्धि से प्राप्त धन किसी स्वतंत्र अर्थपालिका के निर्देशानुसार खर्च करने को वाध्य हो ऐसी व्यवस्था होनी चाहिये। अभी तात्कालिक रूप से अधिकतम निजीकरण का समर्थन और राज्य की शक्तियों का आर्थिक मामलों में हस्तक्षेप कम होना ही व्यावहारिक दृष्टिकोण होना चाहिये।

मंथन कमॉक–110 ''हमारी प्राथमिकता चरित्र निर्माण या व्यवस्था परिवर्तन

कुछ निष्कर्ष हैं।

1. मानवीय चेतना से नियंत्रित व्यवहार को चरित्र कहते हैं। चरित्र मानवता और नैतिकता से जुडा हुआ होता हैं;
2. किये जाने योग्य कार्य करना नैतिकता हैं, किये जाने वाले कार्य न करना अनैतिक हैं न करने योग्य कार्य करना अपराध होता हैं;
3. प्रत्येक व्यक्ति किसी व्यवस्था से संचालित होता हैं और व्यवस्था व्यक्ति समूह से जिस समूह में वह स्वयं शामिल होता हैं;
4. व्यवस्था पारिवारिक, समाजिक तथा राजनीतिक होती हैं। तीनों व्यवस्थायें अगल–अगल होते हुये भी एक–दूसरे की पूरक होती हैं;
5. स्वतंत्रता, अनुशासन और शासन का स्वरूप भिन्न–भिन्न होता हैं। स्वतंत्रता व्यक्ति की व्यक्तिगत होती हैं, किसी अन्य से जुडते ही वह अनुशासन में बंध जाती हैं। स्वतंत्रता शासन व्यवस्था से बाध्य होती हैं;
6. प्रत्येक व्यक्ति का यह स्वभाव होता हैं कि वह स्वयं दूसरों से अधिकाधिक स्वतंत्रता चाहता हैं और दूसरों को कम से कम स्वतंत्रता देना चाहता हैं;
7. सारी दुनियां में व्यवस्था का केन्द्रीयकरण हो रहा हैं। राजनीतिक सत्ता समाजिक तथा पारिवारिक व्यवस्था को अपने नियंत्रण में ले रही हैं। व्यक्तिगत स्वतंत्रता भी संकुचित होती जा रही हैं;
8. परंपरागत परिवार व्यवस्था दोषपूर्ण हैं उससे व्यक्ति पर व्यवस्था का अनुशासन तो हैं किन्तु व्यवस्था पर व्यक्ति समूह का नियंत्रण नहीं हैं;
9. साम्यवादी तथा इस्लामिक व्यवस्थायें व्यक्ति को स्वतंत्रता को न मानने के कारण त्यागने योग्य हैं। भारतीय परिवार व्यवस्था संशोधन योग्य हैं और लोकतांत्रिक व्यवस्था अनुकरणीय हैं;
10. व्यवस्था से चरित्र बनता हैं। चरित्र से व्यवस्था नही। जो लोग व्यवस्था में चरित्र को महत्वपूर्ण मानते हैं वे गलत हैं क्योंकि व्यवस्था व्यक्ति से नहीं व्यवस्था से व्यक्ति संचालित होता हैं;
11. नीति निमार्ण में विचार महत्वपूर्ण होता हैं और क्रियान्वय में चरित्र की भूमिका प्रमुख होती हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था में नीति–निमार्ण विधायिका का और क्रियान्वन कार्यपालिका का कार्य माना जाता हैं;
12. संघ परिवार चरित्र को हर मामले में महत्वपूर्ण मानता हैं तो साम्यवाद किसी मामले में चरित्र को महत्वपूर्ण नहीं मानता मेरे विचार से दोनो गलत हैं;
13. यदि व्यवस्था ठीक हो तो हमें चरित्र निमार्ण को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी चाहिये यदि अव्यवस्था या कुव्यवस्था हो तो चरित्र निमार्ण को रोक कर व्यवस्था परिवर्तन का कार्य करना चाहिये;
14. यदि अपराध अनियंत्रित हो तो शराब, जुआ, वैश्यावृत्ति जैसे अनैतिक कार्यो करने वालों से दूरी घटा लेनी चाहिये। चरित्र निमार्ण के प्रयत्न घातक होते हैं;
15. यदि गाडी का ड्राइवर गलत हो तब भी अव्यवस्था होगी और गाडी खराब हो तो भी। वर्तमान समय में व्यवस्था रूपी गाडी ही गडबड हैं इसलिये गाडी ठीक करना आवश्यक हैं।

16. क्या करना चाहिये इसका निर्णय व्यक्ति के चरित्र पर निर्भर करता हैं। न करने योग्य कार्य करने से रोकने का काम व्यवस्था का हैं। चरित्र व्यक्तिगत होता हैं और व्यवस्थाा सामुहिक होती हैं;

वैसे तो सारे विश्व की ही व्यवस्था गडबड हैं क्योंकि जब तक साम्यवाद और इस्लाम से व्यवस्था मुक्त नहीं होती तब तक व्यवस्था में सुधार सम्भव नहीं। सौभाग्य से भारत की व्यवस्था इन दोनों से बहुत कम प्रभावित हैं फिर भी पिछले समय में जो अव्यवस्था विकसित हुयी हैं उसे व्यवस्था परिवर्तन से ही सुधारा जा सफल हैं चरित्र निमार्ण से नहीं। क्योंकि तानाशाही में चरित्र से व्यवस्था सुधरती हैं और लोकतंत्र में व्यवस्था से चरित्र सुधरता हैं। भारत सैकडो वर्षो तक गुलाम रहने के कारण व्यक्ति के नेतृत्व से व्यवस्था के संचालन का अभयस्त हो गया हैं जो उचित नहीं हैं। व्यवस्था निरंतर प्रभावहीन होती जा रही हैं दूसरी ओर अन्ना हजारे, बाबा रामदेव, संघ परिवार, गायत्री परिवार या आर्य समाज पूरी ईमानदारी और सक्रीयता से चरित्र निमार्ण के कार्य में लगे हुये हैं किन्तु औसत चरित्र गिरता जा रहा हैं क्योंकि व्यवस्था दोषपूर्ण हैं और जितनी गति से चरित्र निमार्ण हो रहा हैं उसकी तुलना में कई गुना अधिक चरित्रपतन राजनीतिक व्यवस्था कर रही हैं। कुल मिलाकर चरित्र गिर रहा हैं किन्तु हमारा दुर्भाग्य हैं कि हम व्यवस्था परिवर्तन के महत्व को नहीं समझ पा रहैं हैं। व्यवस्था में भी पारिवारिक आर्थिक, समाजिक व्यवस्था को राजनीतिक व्यवस्था ने इतना गुलाम बना लिया हैं कि सब प्रकार की व्यवस्थाये राजनीतिक अव्यवस्था से प्रभावित हो रही हैं। राजनीतिक व्यवस्था को ठीक किये बिना चरित्र पतन रूक नही सकता भले ही हम चरित्र निमार्ण द्वारा आंशिक रूप से उस पतन को गति को कम कर सके। इसके बाद भी व्यवस्था परिवर्तन के महत्व को न समझकर चरित्र निमार्ण पर अधिकतम शक्ति लगाना ना समझी का कार्य हैं जो हम लगातार किये जा रहैं हैं। राजनीतिक व्यवस्था में भी हमने कई बार ड्राइवर बदलने का प्रयास किया किन्तु गाडी आगे बढकर पीछे ही जा रही हैं क्योंकि हम समझ ही नहीं रहैं हैं कि गाडी खराब हैं ड्राइवर नहीं।

आवश्यकता इस बात की हैं कि महत्वपूर्ण लोगो को चरित्र निमार्ण की तुलना में व्यवस्था परिवर्तन पर अधिक शक्ति लगानी चाहिये और समझना चाहिये कि लोकतंत्र में चरित्र से व्यवस्था नहीं बल्कि व्यवस्था से चरित्र बनता हैं। जब यह अंतिम सत्य हैं कि व्यक्ति के उपर व्यवस्था और व्यवस्था के उपर व्यक्ति समूह अर्थात समाज होता हैं तब हम उल्टी दिशा में चलकर समाज के उपर व्यवस्था और व्यवस्था के उपर व्यक्ति का प्रयोग क्यों करें। उचित होगा कि इस वर्तमान प्रणाली को पलटकर व्यक्ति के उपर व्यवस्था और व्यवस्था और व्यवस्था के उपर समाज का प्रयोग करें।

मंथन कमांक–111'' भारतीय राजनीति कितनी समाज सेवा कितना व्यवसाय

कुछ निष्कर्ष हैं।

1. समाज के सुचारू संचालन के लिये भारत की प्राचीन वर्ण व्यवस्था पूरी दुनियां के लिये आदर्श रही हैं। बाद में आयी कुछ विकृतियों ने इसे नुकसान पहुॅचाया;
2. आदर्श वर्ण व्यवस्था में प्रत्येक व्यक्ति की उपलब्धियां सीमित होती हैं। मार्गदर्शक की सीमा सर्वोच्च सम्मान तक, रक्षक की सर्वोच्च शक्ति तक, पालक की सर्वोच्च सुविधा एवं धन संपत्ति तक तथा सेवक की सर्वोच्च सुख तक होती हैं;
3. आदर्श वर्ण व्यवस्था में प्रत्येक व्यक्ति की प्रवृत्तियां भी अलग–अलग होती हैं। मार्गदर्शक अर्थात ब्राह्मण मर सकता हैं मार नहीं सकता, हृदय परिवर्तन कर सकता हैं डरा नहीं सकता, सत्य छुपा सकता हैं किन्तु झूठ नहीं बोल सकता;
4. आदर्श वर्ण व्यवस्था में रक्षक अर्थात क्षत्रिय कूटनीति का प्रयोग कर सकता हैं बल प्रयोग कर सकता हैं किन्तु उपदेश अथवा प्रवचन नहीं दे सकता। मरने और मारने के लिये तैयार होता हैं;
5. आदर्श वर्ण व्यवस्था में पालक अर्थात वैश्य जनहित में सच छुपा भी सकता हैं और झूठ भी बोल सकता हैं। मरने से भी बचेगा और मारने से भी बचेगा। लालच दे सकता हैं शत्रु को धोखा भी दे सकता हैं किन्तु प्रवचन उपदेश अथवा डर भय नहीं दिखा सकता;
6. वर्तमान भारतीय राजनीति में कोई अच्छा व्यक्ति चुनाव में नहीं जीत सकता। यदि अपवाद स्वरूप जीत भी गया तो अच्छा नहीं रहेंगा और यदि कोई फिर भी अच्छा रह गया तो जल्दी ही निकाल दिया जायेगा;
7. नीति निर्धारण में विचार महत्वपूर्ण होते हैं चरित्र नहीं। क्रियान्वन में चरित्र का महत्व हैं विचारों का नही;

8. जो कुछ पुराना हैं वह सब सही हैं अथवा जो कुछ पुराना हैं सब गलत हैं ऐसी धारणा उचित नहीं हैं अतिवादी लोग ऐसी धारणा बनाकर उसे स्थापित करने का प्रयत्न करते हैं;
9. भारत की प्राचीन राजतंत्र प्रणाली आदर्श नहीं हैं, राजतंत्र या तानाशाही की तुलना में लोकतंत्र अधिक अच्छा हैं किन्तु अपर्याप्त और असफल हैं। लोकतंत्र की जगह लोक स्वराज अधिक अच्छी प्रणाली हैं;
10. प्राचीन समय में ज्ञान और त्याग को अधिक सम्मान प्राप्त था। मध्यकाल में राजशक्ति और धनशक्ति ने ज्ञान और त्याग को प्रतिस्पर्धा से बाहर कर दिया। दस वर्ष पूर्व तक भारत में गुण्डा शक्ति सर्वोच्च स्थान पर थी जो अब कमजोर हो रही हैं;
11. व्यवसाय के माध्यम से तीन प्रकार के लोग आगे बढते हैंः–1. जो सेवा के उद्देश्य से बिना लाभ हानि के लागत मूल्य पर व्यापार करते हैं 2. जो उचित लाभ लेकर तथा नैतिकता के आधार पर व्यापार करते हैं 3. जो मिलावट और कमतौल के माध्यम से अनैतिक व्यापार करते हैं।

राजनीति में भी तीनों प्रकार के लोग होते हैं। कुछ लोग बिना लाभ–हानि के राजनीति करते हैं। कुछ लोग भ्रष्टाचार की राजनीति करते हैं तो कुछ लोग राजनीति में हत्या, डकैती जैसे अपराधों का भी सहारा लेते हैं। भारतीय राजनीति में वर्तमान समय मे तीसरे प्रकार के लोग अधिक आगे बढते देखे गये हैं। पहले प्रकार के लोगों की असफलता को देखकर अब राजनीति में अच्छे लोगों का आकर्षण खत्म हो गया हैं क्योंकि व्यापार और राजनीति अथवा धन और सत्ता का पूरी तरह घालमेल हो गया हैं। सत्ता धन के साथ सामंजस्य बिठाकर चल रही हैं तो पूंजीपति भी सत्ता को अपने हाथ में रखने का पूरा प्रयास कर रहे हैं।

भ्रष्टाचार करना राजनेताओं की कुछ मजबूरी भी बन गया हैं। चुनाव में बेतहाशा खर्च करना पडता हैं। कार्यकर्ता आधारित चुनाव व्यवस्था होने के कारण कार्यकर्ताओं को भी खुश रखना पडता हैं। उन पर खर्च भी करना पडता हैं और उनके अवैध कार्य को संरक्षण देना भी मजबूरी बन गया हैं। परिवार, रिश्तेदार और मित्र भी बहुत अपेक्षा रखते हैं। इसलिये बिरले लोग ही स्वयं को भ्रष्टाचार से मुक्त रख पाते हैं। मैंने स्वयं देखा हैं कि चालीस वर्ष पूर्व जब मैं राजनीति में अच्छे पदों पर था तब मेरे साथ सक्रिय साथियों की आर्थिक स्थिति बहुत दयनीय थी। हमारे जिले के लोग विकास में बहुत पीछे होते हुए भी संतुष्ट थे। फिर भी हमारे सब साथी पूरी तरह ईमानदार रहे। आज उसी तरह के राजनीतिक पद रखने वालों की आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत हैं क्षेत्र भी बहुत विकसित हुआ हैं फिर भी शायद ही कोई ईमानदार हो। यहॉ तक कि पार्टी के लिये बेइमानी करने को ईमानदारी ही माना जाता हैं किन्तु ऐसा भी व्यक्ति मिलना मुश्किल हैं। बाद मे मैनें स्वयं प्रयोग किया और रामानुजगंज शहर का नगरपालिका अध्यक्ष बना तब मेरे सामने भी ऐसी ही मजबूरी आयी मैंने भी अपने मतदाताओं से सलाह लेकर दस प्रतिशत भ्रष्टाचार की छूट प्रदान की। सोचा जा सकता हैं कि राजनेताओं के सामने भी कुछ मजबूरियॉ हैं और मतदाताओं के सामने भी। यदि किसी साधारण भ्रष्ट को किसी तरह हटने के लिये सहमत भी कर लिया जाये तो आगे आने वाला उससे कई गुना अधिक भ्रष्ट होना निश्चित दिखता हैं। ऐसे में मतदाता के पास क्या विकल्प हैं।

मैंने सन 55 से 84 तक पच्चीसों बार चुनावों का संचालन किया हैं और हर चुनाव में मतदाताओं को पैसा, शराब अथवा अन्य किसी प्रकार से उपकृत करना पडा हैं। मैंने तो एक बार मतदाताओं को सलाह दी थी कि यदि राजनीति पूरी तरह व्यवसाय बन गयी हैं तो आप किसी अच्छे या कम भ्रष्ट को प्राथमिकता दे। यदि ऐसा न हो तो ऐसा कोई चुने जो आपका अच्छा परिचित हो और सुख दुख के समय में काम आ सके और फिर भी कोई नही हैं तो तत्काल जो भी मिले तो वह ले लेना कोई अपराध नहीं हैं क्योंकि जब राजनीति व्यवसाय हैं तब मुफ्त में वोट देने की मूर्खता क्यों की जाये। इतना अवश्य ध्यान रखना चाहिये कि किसी अपराधी या हत्यारें को किसी भी परिस्थिति में वोट न दिया जाये। वोट की सौदेबाजी कोई गलत कार्य नहीं हैं।

मेरे विचार से भारत की राजनीति पूरी तरह व्यवसाय बन गयी हैं और सबसे खतरनाक इसका अपराधीकरण की तरफ बढना हैं। अपराध मुक्त करना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता हैं फिर भी यह स्थिति आदर्श नही हैं और इसे पूरी तरह बदलना चाहिये। जो लोग मतदाताओं को बदलना चाहते हैं वे भी कहीं न कही नासमझ हैं जो लोग राजनेताओं को बदलना चाहते हैं वे भी या तो ढोंग कर रहैं हैं या गलती। न मतदाता बदल सकता हैं न ही राजनेता। हमें तो पूरी राजनीति को बदलना पडेगा और जब तक पावर इकठ्ठा होता रहेगा तब तक राजनीति का व्यवसायीकरण नहीं रोका जा सकता। यदि राजनेताओं की संवैधानिक शक्ति

विकेन्द्रित हो जाये तो सारी समस्याओं का एक साथ समाधान हो सकता हैं न राजनेताओं को सुधारना पडेगा और न मतदाताओं को। इसलिये मेरा मत हैं कि हमे अन्य सब कार्य छोडकर राजनीतिक सत्ता के विकेन्द्रीयकरण की दिशा में आगे बढना चाहिये।

राजनीति बन गयी तवायफ नेता हुये दलाल,
ऐसे में क्या होगा भैया इस समाज का हाल,
संसद को एक पलंग समझ कर उस पर शयन किया
संविधान को मानकर चादर खींचा ओढ़ लिया
अब तक हमने बहुत सहा अब सहेंगे नहीं हम, चुप रहेंगे नहीं चादर हटा देंगे हम, सब कुछ दिखा देंगे हम, कचरा जला देंगे हम !!!!!
मंथन का अगला विषय ''धर्म और सम्प्रदाय का फर्क''

समाजसेवी भाई श्री उत्तम सिंह असवाल जी जीवन परिचय

उत्तराखण्ड के टिहरी गढवाल जिले में ग्राम सभा–मालगडी पट्टी पोस्ट बडियार गढ के एक गरीब पृष्ठभूमि के कृषक परिवार में जन्मे उत्तम सिंह असवाल जी आज समाजिक, खेल–कूद एवं अभिनय के क्षेत्र में एक जाना पहचाना नाम है। उत्तम सिंह असवाल जी का जन्म 25 जून 1979 को मालगडी गांव में हुआ। उत्तम सिंह जी के दो भाई व एक बहन है। वह घर में सबसे बडे है। उनके एक अनुज भाई रवीन्द्र सिंह असवाल जी का अपना मेडिकल स्टोर है तथा दूसरे अनुज, भाई सुनील सिंह असवाल जी ट्रान्सपोर्ट का बिजनेस है। उनके पिता श्री दर्शन सिंह असवाल जी खेतीबाडी के साथ–साथ ड्राइवर का भी काम किया करते थे उनकी माता श्रीमति शकुन्तला देवी जी गृहणी है। असवाल जी की छोटी बहन शादीशुदा एवं गृहणी है। उत्तम असवाल जी की धर्मपत्नी श्रीमति वर्षा असवाल जी एमकॉम, बीएड व योग से पोस्ट ग्रेजुएट तथा परिवार की मंहती जिम्मेदारी एक गृहणी के रूप में निर्वाहन कर रही है। उत्तम जी के दो बेटे है बडे बेटे का नाम नैतिक असवाल और छोटे बेटे का नाम उत्कर्ष असवाल है। उत्तम सिंह असवाल जी एवं उनके दोनो अनुज एक साथ संयुक्त परिवार के रूप में रह रहे है। बचपन से ही उत्तम सिंह असवाल जी का कृषि कार्य के प्रति विशेष रूचि रही है, वह अपने गांव में कई परिवारों के खेत जोत दिया करते थें। उत्तम सिंह असवाल जी ने अपनी 10वीं की शिक्षा सन् 1995 में राजकीय इंटर कॉलेज धद्दी घडियाल टिहरी गढवाल से, 12 वीं सन् 1997 में श्री भरत मंदिर इंटर कॉलेज, ऋषिकेश, एवं स्नातक सन् 2000 में पी.जी. कॉलेज से उत्तीर्ण की है छात्र जीवन में उत्तम जी का सपना भारतीय सेना में जाकर देश सेवा करना रहा था। वर्तमान में आपका अपना ऋषिकेश में थोक विक्रेता दवाईयों का कारोबार है। शिक्षा पूर्ण करने के बाद असवाल जी की सामाजिक क्षेत्र में कार्य करने की रूचि बढी तथा उन्होंने सामजिक, खेल, शिक्षा, स्वास्थ्य, सांस्कृतिक, पर्यावरण आदि क्षेत्र में सक्रिय भूमिका निभायी है। आप प्रतिवर्ष उपरोक्त सामाजिक क्षेत्रों में उत्तराखण्ड के उभरते हुये प्रतिभावान खिलाडियों, साहित्यकर्मियों, स्वास्थ्य के क्षेत्र मे कार्यरत कर्मचारियों, पत्रकारों आदि का अभिनंदन करते रहे है। इनकी संवेदनशीलता का ही एक उदाहरण यह भी है कि आप उत्तराखण्ड के विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिवर्ष अपने अभिन्न मित्र एवं साथी डॉ राजे सिंह नेगी जी के सहयोग से स्वास्थ्य कैम्पों का आयोजन करवाते रहते है तथा निर्धन परिवार के बच्चों को ऋषिकेश में स्थित उडान स्कूल के माध्यम से शिक्षा दिलवाने का पूरा प्रयास करते है। अभी तक अनेकों बच्चों की शिक्षा, दीक्षा की आपने व्यवस्था सुनिश्चित की है। व्यवस्था परिवर्तन मंच के माध्यम से अब तक ऋषिकेश को जिला बनाने तथा ऋषिकेश में डिग्री कॉलेज की मांग एवं हरिद्वार तक आने वाली सभी ट्रेनों को ऋषिकेश तक लाने के साथ–साथ, पूरे प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में चिकित्सकों की नियुक्ति एवं एम्स में स्थानीय लोगों की नियुक्ति तथा एम्स में इलाज की बढ़ाई गई दरों को कम करने जैसे स्थानीय महत्वपूर्ण मुद्दों पर डॉक्टर नेगी जी के नेतृत्व में उत्तम सिंह असवाल जी व उनकी टीम द्वारा आमरण अनशन एवं आंदोलन किए जा चुके हैं।

उत्तम सिंह असवाल जी धार्मिक प्रवृत्ति के भी है। उनके क्षेत्र में घंटाकर्ण देवता का मंदिर है जिसके बारे में कहा जाता है कि श्री बद्रीनाथ भगवान के दर्शन से पहले श्री घंटाकर्ण देवता के दर्शन करने होते है व असवाल जी द्वारा अपने ग्रामवासियों के सहयोग से श्री घंटाकर्ण देवता एवं श्री चन्द्रणांग देंवता (चन्दनीनाग) के मंदिर का नवनिर्माण किया तथा उन्होंने वहॉ 10 दिन का भव्य राजकाज कार्यक्रम करावकर एक डोक्यूमेंट्री फिल्म का निर्माण करवाया है। आप प्रति वर्ष 7 जनवरी को अपने क्षेत्र धद्दी घडियाल में अमर शहीदों व आंदोलनकारियों की याद में देशभक्ति व श्रद्धाजंलि के कार्यक्रम व ब्लॉक स्तरीय एवं जिला स्तरीय विभागों बुलाकर क्षेत्र में कैम्प आयोजित कर ''क्रांति दिवस'' के रूप में मनाते है। टिहरी गढवाल की राजशाही को खत्म करवाने एवं चिपको आंदोलन की शुरूआत भी उन्हीं के गांव से हुई वहॉ वह हर वर्ष चिपको आंदोलन की स्मृति में प्रदेश स्तर के कार्यक्रमों का आयोजन करवाते है। ओ.एन.जी.सी व एचआरडी मिनिस्ट्री के सहयोग से विभिन्न क्षेत्रों के ख्याति प्राप्त वैज्ञानिकों

को आमंत्रित कर स्कूल के छात्र–छात्राओं को विज्ञान के प्रति जागरूक करने का भी सत्त प्रयास करते है। प्रर्यावरण संरक्षण से पहाडी क्षेत्र में स्वरोजगार को बढावा देने के उद्देश्य से अभी तक 5000 से अधिक फलदार वृक्ष जिसमें एक हजार से ज्यादा अखरोट के पेडों का वृक्षारोपड करवा चुके है। प्रतिवर्ष एक तरफ जहॉ असवाल जी प्रतिभावान छात्र–छात्रओं को प्रोत्साहित करते है तो वहीं नवोदय विद्यालयों तथा अन्य विद्यालयों के उन शिक्षकों को भी सम्मानित भी करते है जो अपना शतः प्रतिशत परिक्षा परिणाम दे रहे है।

वर्तमान में उत्तम सिंह असवाल जी गढवाल महासभा उत्तराखण्ड के प्रदेश महासचिव, उडान स्कूल में उप निदेशक, बडियार गढ, कीर्तिनगर ब्लाक के क्षेत्र पंचायत सदस्य, ज्ञान यज्ञ व व्यवस्था परिवर्तन के जिला संयोजक के रूप में सक्रिय सामाजिक भूमिका निभा रहे है। सामाजिक क्षेत्र ये किये गये उत्कृष्ट योगदान के लिये भाई उत्तम सिंह असवाल जी को अनेको बार स्थानीय एवं प्रदेश स्तर पर विभिन्न संस्थानों द्वारा सम्मानित किया गया है।

उत्तम सिंह असवाल जी गढवाल महासभा के माध्यम से उत्तराखण्ड के सभी शासकीय एवं अशासकीय विद्यालयों में गढवाली कुमाउंनी एवं जौनसारी राज्य की बोली को पढाने की मांग प्रदेश शासन से कर रहे है। जिले में सिनेमाघर एवं गढवाल व कुमाउं भवन का निर्माण की भी मांग को लेकर लगातार संघर्षरत है। अपने सामाजिक कार्यो के दौरान आपका आचार्य पंकज जी के माध्यम से प्रख्यात मौलिक विचारक एवं चिंतक श्री बजरंग मुनि के सान्धिय में मुनि जी से जुडकर ऋषिकेश के जिला संयोजक के रूप में ज्ञान यज्ञ प्रसार में सहयोग कर रहे है। बजरंग मुनि सामाजिक शोध संस्थान के प्रबंधकीय कार्यालय की व्यवस्था में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है। प्रत्येक रविवार बजरंग मुनि सामाजिक शोध संस्थान के प्रबंधकीय कार्यालय पर आहुत होने वाले 'ज्ञान यज्ञ' कार्यक्रम का सुचारू संचालन उत्तम सिंह असवाल जी के द्वारा ही किया जा रहा है। उत्तम सिंह असवाल को 'ज्ञान यज्ञ' की तरफ से हार्दिक धन्यवाद एवं शुभकामनाएं।

–अभ्युदय द्विवेदी, राष्ट्रीय संयोजक, ''ज्ञान यज्ञ''।

प्रश्नोत्तर

नरेन्द्र सिंह कछवाहा, कांकरोली, राजस्थान

प्रश्न 1. –लम्बे समय बाद पत्र लिख रहा हूँ। ज्ञान–तत्व क्रमांक–380 प्राप्त हुआ। वर्ण–व्यवस्था संबंधी प्राचीन एवं अर्वाचीन व्यवस्था तथा महिलाओं के बारे में आपके विचार जाने। बहुत कुछ विचार अनुकूल लगे।

आपका ''मंथन'' चल रहा है। मेरे भी अपने कुछ विचार हैं। यदि आप तथा आपके सहयोगी उचित समझें तो निम्नलिखित महत्वपूर्ण मुद्दों पर अवश्य विचार करें और ज्ञान–तत्व में प्रकाशित करें। यथा–

1. क्यों नहीं भारत का एक रूप्या अन्य किसी भी देश (अमेरिका के डॉलर व इंग्लैंड के पौंड, चीन के येन सहित) एक मुद्रा के बराबर घोषित कर व्यवहार में अपनाया जाये। याने एक रूपया बराबर एक विदेशी कोई भी मुद्रा की अर्थव्यवस्था को भारत अपनाये।
2. भारत को कुर्सी–प्रधान देश बनाने का प्रयास सोनिया गांधी, डॉ मनमोहन, राहुल गांधी सहित नरेन्द्र मोदी कर रहे हैं। भारत की भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक व सांस्कृतिक व्यवस्था तथा निरन्तर बढती हुई आबादी का तकाजा है कि भारत वैश्विक–व्यवस्था को छोड कर, भारत की अपनी आर्थिक–व्यवस्था के अनुरूप मापदंड तय करके भारत को पुनः कृषि प्रधान, पशु पालन, कृषि व अन्य गृह लघु उद्योगों का देश बनाया जाये। ऐसी व्यवस्था होने पर ही ग्रामीण क्षेत्र व कृषि का विकास संभव होगा तथा गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी का समाधान हो सकेगा।
3. ब्रिटेन व अन्य देशों द्वारा अपने उपनिवेशों को स्वतंत्र करने, द्वितीय महायुद्ध के परिणामों, रूस के विखण्डन तथा अमेरिका में डोनाल्ड ट्रम्प के राष्ट्रपति बनने के बाद जो संरक्षणवाद का श्री गणेश हुआ है, ऐसे में भारत को भी अपने नागरिकों की चिन्ता करनी चाहिए। लगभग 70–72 प्रतिशत आबादी ग्रामीण क्षेत्र में निवास करती है, शेष नगर–क्षेत्र में निवास करती है। लेकिन राजकीय योजनाएं सभी नगर क्षेत्र को आधार मान कर ही बनाई जा रही हैं क्योंकि राजकीय योजनाएं बनाने वाले ग्रामीण जीवन नहीं जीते, शहरी जीवन जीते हैं। ऐसी स्थिति में भारत सरकार, मतदाताओं, नागरिकों की सोच वैश्विक स्तर को अपनाने की नहीं होकर, राष्ट्रीय स्तर की होनी चाहिए।
4. यदि वैश्विक स्तर पर विस्तार करना भी है तो 'भारत महासंघ' की स्थापना की जानी चाहिए। जिसमें इन देशों तथा उनके नागरिकों को भारत में अधिकतम सुविधाएं दी जानी चाहिए। जिनका भारत–भूमि से आत्मिक लगाव है, तथा जो भारत की

सीमाओं या उसके निकटस्थ हों। इस प्रकार 'भारत महासंघ' के निर्माण से एक तरफ जहॉ पश्चिमी सभ्यता व संस्कृति का विस्तार रूकेगा, तो दूसरी ओर भारतीय समाज, सभ्यता, संस्कृति और सोच के विस्तार को प्रोत्साहन मिलेगा। भारत मजबूत होगा तथा चीन, अमेरिका आदि देशों की विश्वस्तर पर वर्चस्व की जो प्रतिस्पर्धा हो रही है, उसमें कमी आएगी।
आशा है, इन मुददों पर भी विचार कर ज्ञान–तत्व में प्रकाशित करेंगे। चाहे विचार इन मुददों के अनुकूल हों या प्रतिकूल। किन्तु विचार अवश्य किया जाना चाहिए।
उत्तर 1– मुद्रा का आंतरिक मूल्य गिरने के कई कारण होते है। उनमें मुख्य होता है सरकार द्वारा अतिरिक्त मुद्रा प्रसार। सरकारें अपना खर्च पूरा करने के लिए जो अतिरिक्त मुद्रा प्रसार करती है वह एक प्रकार का अघोषित कर होता है। उसके कारण मुद्रा स्फीति होती है। किसी देश में यदि व्याज दर अधिक है तो वह भी मुद्रा के अवमूल्यन में सहायक होती है। वैसे यदि मुद्रा का मूल्य सौ रूपये बराबर एक रूपये भी कर दिया जाये तो आतंरिक व्यवस्था में कोई अंतर नहीं आयेगा। मंहगाई का सामान्य जन जीवन पर कोई अच्छा बुरा प्रभाव नहीं पडता क्योंकि मुद्रा एक माध्यम है मूल नहीं। प्रभाव मूल का पडता है माध्यम का नहीं।
उत्तर 2– मैं आपसे सहमत हूॅ। वर्तमान मोदी सरकार इस दिशा में बढने का ईमानदार प्रयास कर रही है।
उत्तर 3– अब तक दुनियां राष्ट्रीयता की जगह विश्वस्तरीय मानवता को प्रोत्साहित करने का प्रयास कर रही थी। मुस्लिम संगठनों ने इस प्रयास का विश्वस्तरीय दुरूपयोग किया परिणाम स्वरूप दुनियां में मुस्लिम संगठनों के प्रति सतर्कता बढ रही है जिसे राष्ट्रवाद के रूप में देखा जा रहा है। भारत भी इस दिशा में निरन्तर सक्रिय है। मैं ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त करने के लिए कृत्रिम उर्जा की भारी मूल्य दर वृद्धि का पक्षधर हूॅ।
उत्तर 4– मेरे विचार से एक विश्व महासंघ बनना चाहिए जिसमें दुनियां के प्रत्येक व्यक्ति अपना वोट देकर विश्व संविधान बनाने में सहभागी हो सके। जब तक ऐसी शुरूआत नहीं होती तब तक हम भारत से ही ऐसी शुरूआत करे। जिसमें भारत का प्रत्येक व्यक्ति भारतीय संविधान निर्माण में अपनी भूमिका अदा कर सके महासंघ बनाने से पहले हम भारतीय स्वंतत्रता को तो तंत्र के चंगुल से मुक्त करा ले।
अब हम सब लोग ऋषिकेश कार्यालय से बजरंग मुनि समाजिक शोध संस्थान तथा ज्ञान यज्ञ परिवार का संचालन कर रहे है। ग्राम संसद अभियान सहित अन्य समूह कौशाम्बी कार्यालय से संचालित हो रहे है। आगामी दो और तीन फरवरी 2019 को नोएडा धर्मशाला में राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित है। इस सम्मेलन में अधिक से अधिक साथियों को आना चाहिए।

प्रश्न 1. –वर्ण व्यवस्था में कौन सी गंभीर विकृति आई जिसके कारण इतना नुकसान हुआ।
उत्तर– वर्ण व्यवस्था गुण, कर्म, स्वभाव के आधार पर निश्चित होती थी जन्म के आधार पर नहीं। उसके लिये विधिवत परीक्षा होती थी। बाद में धीरे–धीरे परीक्षाएं बन्द हो गई तथा वर्ण जन्म के आधार पर बनने लगे। वह बदलाव ही गंभीर विकृति के रूप में बढता चला गया।
प्रश्न 2. –यदि मार्गदर्शक को ही राजनैतिक पद दे दिया जाये तो क्या नुकसान होगा।
उत्तर– मार्गदर्शक की योग्यताएं रक्षक अर्थात क्षत्रिय से बिल्कुल अलग होती हैं। मार्गदर्शक कूटनीति का प्रयोग नहीं कर सकता। हिंसा से भी परहेज करता है तथा दयालु स्वभाव का होता है। यदि मार्गदर्शक ही रक्षक का भी काम करेगा तो वह न तो ठीक से मार्गदर्शन कर पायेगा न ही रक्षा कर सकेगा। हम सारी शक्ति एक स्थान पर इकठठी करने की भूल क्यों करें। शक्ति को बंटना उचित होगा।

प्रश्न 3.–क्या मार्गदर्शक अर्थात ब्राहम्ण जनहित में भी झूठ नहीं बोल सकता। यदि कसाई से गाय बचाने के लिये ब्राहम्ण को झूठ बोलना पडे तो क्या गलत है।

उत्तर– मार्गदर्शक अर्थात ब्राम्हण को हृदय परिवर्तन तक ही सीमित रहना चाहिये। वह झूठ बोलेगा तो झूठ पकड में आ जायेगी क्योंकि उसका प्रशिक्षण उस तरह का नहीं है। कसाई द्वारा गाय की जानकारी पूछने पर भी मार्गदर्शक को सिर्फ प्रवचन उपदेश तक ही सीमित रहना चाहिये। बल प्रयोग का काम रक्षक का है अन्य झूठ बोलने का काम पालक अर्थात वैश्य का। किसी गाय की रक्षा के लिये मार्गदर्शक अर्थात ब्राम्हण के लिये उचित होगा कि वह भले ही सत्य छिपा ले किन्तु झूठ बिल्कूल न बोलें। सभी वर्ण के लोगों को अपनी अपनी योग्यतानुसार सीमाओं में रहकर ही काम करना चाहिये। स्व धर्मे

निधनं श्रेयः पर धर्मो भयावहः।

प्रश्न 4. –राजनीतिज्ञ समाज सुधार का काम कर सकते है कि नही।

उत्तर– राजनीतिज्ञ सिर्फ रक्षक मात्र होता है मार्गदर्शक नहीं। राजनेता व्यक्तिगत रूप से भले ही कुछ भी करे किन्तु राजनेता के रूप में समाज सुधार या व्यापार नहीं करना चाहिये। समाज सुधार का काम मार्गदर्शक अर्थात ब्राम्हण तक सीमित है। वर्तमान समय में सरकार समाज सुधार तथा व्यापार भी करने लग गई जो विदेशों की नकल मात्र है। सरकार को सिर्फ न्याय सुरक्षा तक सीमित रहना चाहिये।

प्रश्न 5. –क्या पालक अर्थात वैश्य अपने स्वार्थ में भी झूठ बोल सकता है।

उत्तर– पालक अर्थात वैश्य जनहित में झूठ बोल सकता है किन्तु अपने व्यक्तिगत स्वार्थ में उसे झूठ नहीं बोलना चाहिये। उसे मार्गदर्शक तथा रक्षक अर्थात सरकार से झूठ नहीं बोलना चाहिये किन्तु व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा में वह यदि कुछ झूठ का सहारा लेता है तो वह अनैतिक नहीं है। वर्तमान भारत में राजनेता व्यापार कर रहे हैं इसलिये उनसे झूठ बोलना अनैतिक नहीं। वर्तमान भारत में सरकार अर्थात राजनैतिक व्यवस्था ने पूरे समाज को गुलाम बना लिया है। जब तक संविधान तंत्र का गुलाम है तब तक समाज स्वतंत्र नहीं। ऐसी संवैधानिक व्यवस्था से टैक्स चोरी करना अनैतिक कार्य नहीं है। भले ही गैर कानूनी क्यों न हो। मंदिर धर्मशाला या अन्य किसी सामाजिक संस्था से झूठ बोलना अनैतिक है किन्तु सरकार सामाजिक संगठन के स्वरूप में तब तक नहीं जब तक संविधान के अन्तर्गत पूरा तंत्र काम करने को बाध्य न हो।

प्रश्न 6. –क्या राजनीति से सभी अच्छे लोगो को बाहर हो जाना चाहिए।

उत्तर– सभी धूर्त राजनीति में प्रवेश करने तक अच्छे ही दिखने का नाटक करते हैं। समाज के सामने कोई मापदण्ड नहीं कि वह अच्छे बुरे को पहले ही समझ ले। इसलिये सभी अच्छे लोगो को राजनीति से तब तक दूरी बना लेनी चाहिये जब तक उनका उददेश्य संविधान को मुक्त कराने की प्राथमिकता से न जुडा हो।

प्रश्न 7. –यदि निर्धारण में भी चरित्रवान हो तो क्या गलत होगा।

उत्तर– चरित्र का महत्व तो सब जगह है किन्तु विधायिका और कार्यपालिका की तुलना में कार्यपालिका में चरित्र अधिक महत्वपूर्ण है और विधायिका में कम। संसद में अच्छे लोग जायें यह प्रयत्न बेकार की कसरत है ऐसा प्रयत्न न संभव है न उचित।

प्रश्न 8. –वर्तमान समय में किस प्रकार के लोग अधिक ऐसी गलती कर रहे है।

उत्तर– वर्तमान समय में साम्यवादी पुरानी सभी व्यवस्था को गलत मानते हैं और संघ वाले पुरानी सारी व्यवस्था को ठीक।मेरे विचार में वर्तमान परिस्थिति अनुसार समीक्षा करनी चाहिये।

प्रश्न 9. –लोकतंत्र व लोकस्वराज में क्या अंतर है।

उत्तर– लोकतंत्र लोक नियुक्त तंत्र है तो लोक स्वराज्य लोक नियंत्रित तंत्र। लोक स्वराज्य को सहभागी लोकतंत्र कह सकते है और लोकतंत्र संसदीय।

प्रश्न 10. –क्या आप मानते है कि ज्ञान और त्याग महत्वहीन हो गये है।

प्रश्न 11. –क्या वर्तमान समय में राजनीति में अपराधियों का महत्व घटना शुरू हो गया है।

उत्तर–वर्तमान समय में ज्ञान और त्याग का महत्व समाप्त प्राय है। ऐसे लोग हर महत्वपूर्ण स्थान से उपेक्षित हो रहे हैं। सन 91 के पूर्व राजनीति और अपराध के बीच पूरी तरह तालमेल था। धीरे–धीरे कुछ बदलाव है। पिछले पंद्रह बीस वर्ष से कुछ और सुधार है। वर्तमान भारतीय राजनीति में जिस तरह मोदी, राहुल, नीतिश, अखिलेश आदि आगे तथा ममता, माया, लालू, दिग्विजय, मुलायम, रामविलास पासवान आदि महत्वहीन हो रहे हैं वह भी शुभ लक्षण है। न्यायालय भी अपराधियों के विरूद्ध अधिक कडा हो रहा है। साम्यवाद का पतन भी शुभ लक्षण है।

प्रश्न 12. –जो लोग मिलावट और कमतोल से दूर रहते है किन्तु मजबूरी का लाभ उठाकर अधिक मुनाफा लेते है। उन्हें आप क्या मानेगें।

उत्तर–व्यापार में अधिक मुनाफा लेना कोई अनैतिक या अपराध नहीं है। मिलावट और कमतौल अपराध है। इसलिये व्यापार में मुनाफा अधिक लेने की कोई बडी समस्या नहीं है।

प्रश्न 13. –राजनीति को कैसे बदला जा सकता है क्योंकि राजनीति तो राजनेता ही बदलेगे।
उत्तर–वर्तमान संविधान के अनुसार राजनीति पर राजनेताओं का एकाधिकार है। हम राजनीति में सुधार की बात न करके व्यवस्था परिवर्तन की बात कह रहे हैं। इसका आशय संविधान की तंत्र के एकाधिकार से मुक्ति है। जब संविधान मुक्त होगा तब राजनेताओं का एकाधिकार नहीं रहेगा।

प्रश्न14. –इस कार्य की पहल कहॉ से हो सकती है।
उत्तर–इस कार्य की पहल संविधान संशोधन के असीम अधिकारों को तंत्र से निकालकर किसी अन्य समाज नियंत्रित व्यवस्था को देने से हो सकती है।

प्रश्न 15. –कुछ लोग पार्टी के लिये भ्रष्टाचार करते है अपने लिये नहीं उन्हें क्या माना जाये।
उत्तर–वर्तमान समय में पूरे समाज में भ्रष्टाचार का ग्राफ बहुत उपर है। ऐसे समय में पूरी तरह ईमानदारी की उम्मीद व्यर्थ है। यदि कोई नेता व्यक्तिगत रू‍प से ठीक है तो उसे ईमानदार मानना चाहिये। इसीलिये हम मनमोहन सिंह, अटल ली, मोदी जी, को ईमानदार मानते है।

प्रश्न 16. –आपके विचार में धन राजनीति को अधिक प्रभावित कर रहा है अथवा राजनीति धन को । दोनों में कौन अधिक प्रभावशाली है।
उत्तर–मेरे विचार में धन की तुलना में राजनीति की शक्ति और प्रभाव बहुत ज्यादा है। धन वालों के पास पावर नहीं किन्तु पावर के साथ धन जुड जाता है। मायावती जी के पास पावर के बाद धन आया धन के बाद पावर नहीं। धन पावर में सहायक है भूल नहीं।

प्रश्न 17. –वर्तमान समय में राजनीति में भ्रष्टाचार पूरे समाज के औसत भ्रष्टाचार से अधिक है या कम।
उत्तर–वर्तमान समय में समाज की तुलना में राजनीति में भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा है। समाज में सामाजिक मामलों में आधे से ज्यादा लोग ईमानदार है किन्तु राजनीति में ऐसे व्यक्ति शायद ही मिल सकें।

प्रश्न 18. –ऐसा क्यों हुआ कि अब धीरे–धीरे लोग सम्पन्न होते हुये भी भ्रष्ट होते जा रहे है।
उत्तर–व्यक्ति का चरित्र नहीं गिरा है बल्कि दोषपूर्ण राजनैतिक व्यवस्था ने चरित्र गिराया है। भ्रष्टाचार सत्ता के केन्द्रीयकरण का परिणाम है। इसलिये चरित्र निर्माण के पूर्व संवैधानिक राजनैतिक व्यवस्था परिवर्तन का काम पहले होना चाहिये।
प्रश्न 19. –आप चरित्र निर्माण और राजनैतिक व्यवस्था में सुधार के विरूद्ध क्यों है।
उत्तर–जब तक तंत्र को लोक नियंत्रित नहीं किया जाता तब तक सारे प्रयत्न बेकार हैं। पेड से बंधी नाव की रस्सी खोले बिना नाव चलाना बेकार की कसरत है। संविधान तंत्र का गुलाम है और हम समाज सुधार की बात कर रहे हैं।
प्रश्न 20. –राजनीति में भ्रष्टाचार अधिक बढा है अथवा अपराधीकरण।
उत्तर–पहले अपराधीकरण बढा था अब भ्रष्टाचार। वैसे मोदी सरकार के बाद कुछ भ्रष्टाचार भी कम होना शुरू हुआ है।
प्रश्न 21. –क्या राजनीति में चरित्र निर्माण के प्रयत्न ढोंग है। यदि हॉ तो कैसे?
उत्तर–राजनीति में चरित्र निर्माण न संभव है न उचित। व्यवस्था परिवर्तन ही एकमात्र मार्ग है।